नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 111
दि. 21.08.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

संक्षिप्त समाचार

यूआईडीएआई ने आधार-आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए स्टारलिंक को शामिल किया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रदाता स्टारलिंक सैटेलाइट

कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को अपने साथ जोड़ लिया है। स्टारलिंक ग्राहक सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करेगा। इससे पूरी प्रक्रिया सुचारू, सुरक्षित और बहुत आसान हो जाएगी।

पीएम 22 अगस्त को बिहार और प. बंगाल का दौरा करेंगे

पीएम गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से संबंधित

पीएम गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगा

नए पुल से भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम होगी और सिमरिया धाम तक पहुंचना आसान होगा

पीएम गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे

(जीएनएस)।

पीएम श्री नरेन्द्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वह सुबह लगभग 11 बजे बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद, वे गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे।

पीएम शाम लगभग 4:15 बजे कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद बिमान बंदर तक मेट्रो की सवारी करेंगे और वापस आएंगे। इसके अतिरिक्त, वह कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

बिहार में पीएम कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, पीएम राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। यह पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा।

यह पुल पुराने 2-लेन वाले जर्जर रेल-सह-सड़क पुल "राजेंद्र सेतु" के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। यह नया पुल उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया आदि) और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों (शेखपुरा, नवादा, लखीसराय आदि) के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी।

इससे आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर बिहार, में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं।

यूपी सरकार बोली- कहीं भी उर्वरक की कमी नहीं

खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है. किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है. सरकार ने खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है.

सरकार ने बुधवार को किसानों और व्यापारियों से अनावश्यक जमाखोरी न करने का आग्रह करते हुए दोहराया कि कृषि संबंधी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. एक बयान के मुताबिक, कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी. खरीफ सत्र 2024 में इस अवधि (18 अगस्त) तक 36.76 लाख टन उर्वरक की बिक्री हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक 42.64 लाख टन उर्वरक बेचा जा चुका है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से अपील की है कि खाद का भंडारण न करें. जितनी आवश्यकता है, उतना खाद लें, जब-जब आवश्यकता है, तब-तब खाद लें. हर जनपद में शिकायत प्रकोष्ठ है. किसी भी परेशानी की स्थिति में अवगत कराएं.

उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों को मुख्यमंत्री ने दी कड़ी चेतावनी

मुख्यमंत्री ने उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है. उन्होंने जनपद में तैनात अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण करने, किसानों से संवाद स्थापित करने और समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया है. कृषि विभाग ने बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है. प्रदेश में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल अभी तक अधिक खाद वितरण किया जा चुका है. गत वर्ष 27.25 लाख टन यूरिया वितरण हुआ था, इस वर्ष अभी तक 31.62 लाख टन वितरण किया जा चुका है.

डीपीडीपी अधिनियम, 2023 आरटीआई के तहत पारदर्शिता बनाए रखते हुए गोपनीयता को बरकरार रखता है

(जीएनएस)।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रावधान करता है जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता, दोनों को मान्यता देता है।

डीपीडीपी अधिनियम एक विस्तृत और व्यापक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद पारित किया गया था, जिसके दौरान डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 (डीपीडीपी विधेयक) पर 22,600 से अधिक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, डीपीडीपी विधेयक संसद में पेश किया गया और बाद में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के रूप में अधिनियमित किया गया।

डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में संशोधन, निजता के मौलिक अधिकार को सूचना के अधिकार के साथ जैसा कि न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, संतुलित करता है। यह संशोधन उचित प्रतिबंधों पर स्थापित न्यायिक तर्क के अनुरूप है, मौजूदा न्यायशास्त्र को संहिताबद्ध करता है, और कानूनों के बीच संभावित टकराव से बचने में मदद करता है।

इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के तहत, कोई सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है यदि सूचना के प्रकटीकरण में जनहित अधिक हो, संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से । यह धारा इस प्रकार है:

'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में किसी बात के होते हुए भी या उपधारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी छूट के होते हुए भी, कोई सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित अधिक है संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से ।'

उक्त संशोधन व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध नहीं लगाता; बल्कि, यह व्यक्तियों के निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पारदर्शिता ढाँचा और सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजता ढाँचा, पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, सामंजस्यपूर्ण रूप से अस्तित्व में बने रहें।

खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के उद्घाटन संस्करण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष एथलीट 24 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे

जम्मू और कश्मीर की डल झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की ओपन-एज जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल शीर्ष राज्यों में शामिल

(जीएनएस)।

जम्मू और कश्मीर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव (केआईडब्ल्यूएसएफ) में देश के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलीट 24 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तीन दिवसीय इस आयोजन में 400 से ज्यादा एथलीट नौकायन, कैनोइंग और कयाकिंग जैसी स्पधाओं में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 पहली समेकित ओपन-एज श्रेणी चैंपियनशिप होगी जिसमें सभी 14 कयाकिंग और कैनोइंग स्पधाएँ और 10 रोइंग स्पधाएँ ओलंपिक स्पधाएँ होंगी। वाटर गेम्स के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए, तीन प्रदर्शन स्पधाएँ होंगी - वाटर स्कीइंग, शिखर बोट स्प्रिंग और ड्रैगन बोट रेस।

इस महोत्सव में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। इनमें से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल के एथलीटों पर सबकी नजरें होंगी। प्रतियोगिता प्रबंधक, पूर्व विश्व कप विजेता कैनोइस्ट और ओलंपिक जज, बिलकिस मीर ने कहा, "चूँकि सर्विसेज इन खेलों में एक टीम के रूप में भाग नहीं लेंगी, इसलिए यह देखना अच्छा होगा कि राज्य कैसा प्रदर्शन करते हैं। कोर्स को सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और हम पूरी तरह तैयार हैं।"

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया कैलेंडर में एक नया आयोजन है। 2025 में, दो नए आयोजन जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स मई में दीव में आयोजित किए गए थे। खेलो भारत नीति के अनुसार, वाटर गेम्स और बीच गेम्स, दोनों का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और पर्यटन को आकर्षित करना है।

कयाकिंग और कैनोइंग के लिए, नवंबर में टिहरी (उत्तराखंड) में आयोजित पिछली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को क्वालीफायर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एकल और युगल में शीर्ष 15 और शीर्ष आठ चार खिलाड़ी केआईडब्ल्यूएसएफ में भाग लेंगे। रोइंग के लिए, इस वर्ष मार्च में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के शीर्ष आठ खिलाड़ी भाग लेंगे।

इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले सेना के रोवर अर्जुन लाल जाट मुख्य आकर्षणों में से एक होंगे। 28 वर्षीय जाट ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया है और हांग्जो में 2022 एशियाई खेलों में लाइट- वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीता है।

वाटर स्पोर्ट्स में पुरुषों और महिलाओं का लगभग बराबर प्रतिनिधित्व होगा। पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 409 एथलीटों में से 202 महिलाएँ होंगी। केआईडब्ल्यूएसएफ 2025 में मध्य प्रदेश (44), हरियाणा (37), ओडिशा (34) और केरल (33) का सबसे बड़ा दल होगा। गुजरात, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की टीमें सबसे छोटी होंगी।

गुरुवार को पहले दिन कयाकिंग और कैनोइंग स्पर्धा में खिलाड़ी तीन स्वर्ण पदकों के लिए खेलेंगे। सभी 10 रोइंग फाइनल 23 अगस्त को अंतिम दिन निर्धारित हैं। उद्घाटन समारोह गुरुवार शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे और जम्मू- कश्मीर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।

यह वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के बाद, जम्मू-कश्मीर में दूसरा खेलो इंडिया आयोजन होगा। 2017- 18 में शुरू किए गये खेलो इंडिया खेल अभियान जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक मिशन है और इसका उद्देश्य संगठित प्रतिभाओं की पहचान, संरचित खेल प्रतियोगिताओं और बुनियादी ढाँचे के विकास पर भी केंद्रित है।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने 'पशुधन उत्पादकता बढ़ाने हेतु आयोजित वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम' की अध्यक्षता की

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने आज 'पशुधन उत्पादकता बढ़ाने हेतु वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देशभर के 2000 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से 1 लाख से अधिक पशुपालक किसान जुड़े। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश शामिल रहे।

सहकारी बैंकों के साथ पैक्स का एकीकरण

(जीएनएस)।

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत सभी कार्यरत पैक्स को एक ईआरपी (उद्यम संसाधन नियोजन) आधारित साझा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाया जा रहा है, जो उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ता है। यह साझा ईआरपी सॉफ्टवेयर परियोजना देशभर के सभी पैक्स को प्रदान किया गया है, ताकि पैक्स की सभी प्रकार की कार्यात्मक, ऋण और गैर-ऋण पर डेटा एकत्र किया जा सके। ईआरपी-आधारित साझा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एक साझा लेखा प्रणाली (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से पैक्स संचालन की दक्षता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह शासन और पारदर्शिता को मजबूत करता है जिसके परिणामस्वरूप ऋण वितरण में तेजी आती है। इससे लेनदेन लागत कम होती है, भुगतान असंतुलन

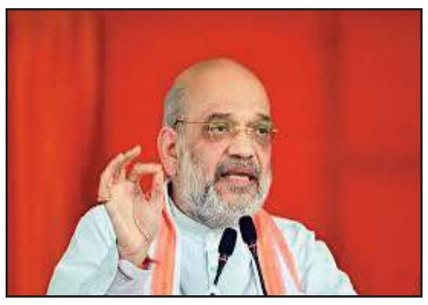

न्यूनतम होता है और डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ लेखांकन बेरोक-टोक होता है।

सहकारी बैंकिंग प्रणालियों के बीच डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतर-संचालन को बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) नामक संगठन की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाकर सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण में तेजी लाना, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य बैंक डिजिटल युग की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

इसके अलावा ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए आरबीआई ने सहकार सारथी (साझा सेवा इकाई) की स्थापना के लिए नाबार्ड को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है ।

पेट्रोल कारों से इलेक्ट्रिक कारों तक: गुजरात बन रहा भारत का ऑटोमोटिव हब

भारत की ऑटो क्रांति का केंद्र उत्तर गुजरात, VGRC के लिए तैयार

गांधीनगर, 20 अगस्त : 7.5 लाख कार यूनिट प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाले सुजुकी मोटर्स के गुजरात प्लांट के साथ, उत्तर गुजरात भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माण केंद्रों में से एक बन चुका है। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए यहाँ मौजूद मजबूत व अनुकूल बुनियादी ढांचा, निवेश-अनुकूल नीतियां और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने इस क्षेत्र को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए आकर्षक केंद्र बना दिया है।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुजुकी मोटर्स ने ₹3,200 करोड़ का निवेश करके अपनी चौथी प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इससे न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि गुजरात में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी सुनिश्चित होगी।

2012 से 2015 के बीच गुजरात में अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के निवेश की एक लहर देखने को मिली। 2014 में सुजुकी द्वारा राज्य में मेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए टङ्कव पर हस्ताक्षर करना

इस निवेश यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। गुजरात उनके इस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरा और इसके बाद से कंपनी ने राज्य में लगातार निवेश किया, जिससे रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न हुए। आज, सुजुकी मोटर्स का गुजरात प्लांट भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माण प्रतिष्ठानों में शामिल है और इसने मेहसाणा क्षेत्र में ऑटो कम्पोनेंट उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश को भी गति दी है।

इसके अलावा, गुजरात की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और यहाँ मौजूद मजबूत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी राज्य को वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। 2024 में राज्य ने लगभग ₹3,459 करोड़ के ऑटो निर्यात में योगदान दिया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, जापान, वअए और चिली प्रमुख निर्यात गंतव्य रहे।

साथ ही, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गुजरात में वित्त वर्ष 2022झ23 में निवेश ₹29,700 करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले पांच वर्षों में 16.4% की मजबूत उअऋक का संकेत देता है। राज्य का मांडलझबेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (रक्फ्र) अब प्रमुख ऑटो-औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है।

हाल ही में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने दो प्रमुख घोषणाएं भी की हैं:

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी प्लांट (₹7,300 करोड़) की स्थापना
- ईवी निर्माण सुविधा (₹3,100 करोड़) की स्थापना

गुजरात को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और आकर्षक प्रोत्साहनों ने अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों का भरोसा लगातार मजबूत किया है। और इसी दिशा में ये पहलें न केवल गुजरात की औद्योगिक क्षमता को नई ऊर्जा देती हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से इसे एक वैश्विक ऑटोमोबाइल पावरहाउस के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर करती हैं।

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य के चलते भावनगर मंडल की कुछ ट्रेनें होंगी प्रभावित

राजकोट मंडल में स्थित लाखाबावल–पीपली–कानालुस सेक्शन में डबल ट्रैक कार्य के चलते 23 अगस्त, 2025 (शनिवार) तक रेल यातायात प्रभावित होगा। भावनगर रेलवे मंडल की प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

रद्द ट्रेनें:

- ट्रेन नं 19251 ओखा–वेरावल एक्सप्रेस 20.08.2025 से लेकर 22.08.2025 तक रद्द रहेगी।
- ट्रेन नं 19252 वेरावल–ओखा एक्सप्रेस 20.08.2025 से लेकर 22.08.2025 तक रद्द रहेगी।

आंशिक रूप से रद्द की गयी ट्रेनें:

- ट्रेन नं 59206 पोरबंदर–कानालुस लोकल तत्काल प्रभाव से 22.08.2025 तक लालपुर जाम–कानालुस के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
- ट्रेन नं 59205 कानालुस–पोरबंदर लोकल तत्काल प्रभाव से 22.08.2025 तक कानालुस–लालपुर जाम के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ट्रेनों का स्टोपेज रद्द होना:

- ट्रेन नं 19209 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 23.08.2025 तक लाखाबावल स्टेशन पर नहीं रुकेगी।
- ट्रेन नं 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 22.08.2025 तक लाखाबावल स्टेशन पर नहीं रुकेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें और ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार कि असुविधा ना हो।

ग्लोबल ट्रावेल एजेंट असोशिएशन (जीटीएए) के साथ भविष्य उन्मुख रेलवे पहल पर अहमदाबाद मंडल का संवाद

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा दिनांक 19.08.2025 को अमदावाद में ग्लोबल ट्रावेल एजेंट असोशिएशन (GTAA) के साथ एक महत्वपूर्ण संवादात्मक एवं सहभागिता सत्र का आयोजन किया गया।

इस सत्र का उद्देश्य भारतीय रेलवे एवं ट्रैवल ट्रेड फ्रैटर्निटी के बीच एक सहयोगात्मक मंच तैयार करना था, जहाँ नए व्यापारिक अवसरों, यात्री सेवाओं, पर्यटन संवर्धन और साझेदारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। यह पहल GTAA के उस मिशन को भी दर्शाती है जिसके अंतर्गत वह ट्रैवल इंडस्ट्री और सरकारी संस्थाओं के बीच संबंधों को सुदृढ़ कर आपसी विकास और व्यापारिक क्षितिज का विस्तार करना चाहता है।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने इस अवसर पर दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे केवल देश की प्रगति का आधार स्तंभ ही नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और पर्यटन संवर्धन की अहम कड़ी भी है। उन्होंने भारतीय रेलवे की दूरदर्शी नीतियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी—जिनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1377 स्टेशनों का पुनर्विकास, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक सेवाएँ शामिल हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी ने कहा कि भारतीय रेलवे निरंतर यात्रियों और पर्यटन क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेषी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने डिजिटल टिकटिंग प्रणाली, मोबाइल ऐप आधारित सुविधाएँ, स्टेशन परिसरों में रेल कोच रेस्टोरंट, प्रीमियम लाउंज, हेरिटेज टूर कियोस्क, एवं यात्रियों हेतु उबर तथा रैपिडो जैसी सेवाओं के सम्मिलन की जानकारी दी।

GTAA (ग्लोबल ट्रावेल एजेंट असोशिएशन) के प्रेसीडेन्ट श्री संकेत शाह ने भारतीय रेल की विकासोन्मुख परियोजनाओं की सराहना की और कहा कि रेलवे के व्यापक नेटवर्क और GTAA की विशेषज्ञता के संयोजन से पर्यटन एवं यात्री सेवाओं को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से स्टेशन परिसरों में विज्ञापन अवसरों, यात्री सेवा केंद्रों, प्रीमियम सुविधाओं एवं हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में भागीदारी की संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

मंडल प्रवक्ता ने बताया कि इस संवादात्मक सत्र में प्राप्त सभी सुझावों को भारतीय रेलवे की भविष्य की योजनाओं में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल रेल सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि यात्रियों के अनुभव को और अधिक समृद्ध एवं संतोषजनक बनाया जा सकेगा।

यह सत्र विचारों एवं सुझावों के आदान–प्रदान का एक प्रभावी मंच सिद्ध हुआ और भारतीय रेल तथा यात्रा व्यापार समुदाय के बीच सुदृढ़ साझेदारी एवं दीर्घकालिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे ने पुनः यह स्थापित किया है कि वह नवाचार, उत्कृष्ट सेवा, सतत विकास और यात्रियों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और यह प्रतिबद्धता भारतीय रेल मंत्रालय की दूरदर्शी सोच तथा राष्ट्र के समग्र विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी और दो जोड़ी गणपति स्पेशल ट्रेन

मुंबई, 20 अगस्त, 2025

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा गणपति के त्‍योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उधना – रत्नागिरी और विश्वामित्री – रत्नागिरी स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर और 2 जोड़ी गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्‍या 09022/09021 उधना–रत्नागिरी साप्ताहिक स्पेशल [6 फेरे]

ट्रेन संख्या 09022 उधना–रत्नागिरी स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को उधना से 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 20:00 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09021 रत्नागिरी–उधना स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को रत्नागिरी से 21:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:20 बजे उधना पहुँचेगी। उपर्युक्‍त जोड़ी ट्रेनें 21 अगस्त से 4 सितंबर, 2025 तक चलेंगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वलसाड, वापी, दहानू रोड, पालघर, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून और संगमेश्वर रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे हैं।

2. ट्रेन संख्या 09120/09119 विश्वामित्री – रत्नागिरी साप्ताहिक स्पेशल [6 फेरे]

ट्रेन संख्या 09120 विश्वामित्री – रत्नागिरी स्पेशल प्रत्येक सोमवार को विश्वामित्री से 08:00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 20:00 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09119 रत्नागिरी – विश्वामित्री स्पेशल प्रत्येक सोमवार को रत्नागिरी से 21:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:45 बजे विश्वामित्री पहुँचेगी। उपर्युक्‍त जोड़ी ट्रेनें 25 अगस्त और 8 सितंबर, 2025 तक चलेंगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, दहानू रोड, पालघर, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून और संगमेश्वर रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2–टियर, एसी 3–टियर, स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे हैं।

ट्रेन संख्या 09022 एवं 09120 की बुकिंग पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि–5 का किया सफल परीक्षण, 7,000 किमी. से अधिक दूर करेगी वार

(जीएनएस)।

भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि–5' का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परीक्षण से भारत के रक्षा क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिली है।

सरकार ने बताया कि मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान की देखरेख में किया गया, जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में पुष्टि की।

यह मिसाइल अग्नि–5 का एक उन्नत संस्करण है, जो भारत की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है। इसकी मारक क्षमता 7,000 किलोमीटर से अधिक है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है।

पिछले साल, भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) क्षमता वाली अग्नि–5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया था। यह तकनीक हथियार प्रणाली को एक साथ कई परमाणु हथियारों से निपटने में सक्षम बनाती है।

जून में यह रिपोर्ट आई थी कि ऊध्र्ड इसकी मारक क्षमता को 7,500 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन में शामिल ऊध्र्ड के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की थी।11 मार्च 2024 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम से अग्नि–5 का पहला एमआईआरवी परीक्षण प्रक्षेपण किया था। इस परीक्षण ने एक साथ कई वारहेड ले जाने और छोड़ने की इसकी क्षमता को मान्य किया।

यह मिसाइल एक साथ तीन परमाणु वारहेड तक ले जाने और फायर करने में सक्षम है। भविष्य में इसमें बंकर–बस्टर बम तकनीक को एकीकृत करने का लक्ष्य है, जिससे बंकर जैसे मजबूत लक्ष्यों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता बढ़ेगी।

भारत के इस परीक्षण से पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान स्थित थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट (एसवीआई) ने प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को चेतावनी दी है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए "गंभीर जोखिम" पैदा करता है।

एसवीआई ने बताया कि 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम (एमटीसीआर) में शामिल होने के बाद भारत के मिसाइल विकास में तेजी आई, जिससे उसे उन्नत प्रणालियों तक पहुंच मिली। थिंक टैंक ने चेतावनी दी कि भविष्य के संस्करण 8,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता के साथ वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग जैसे दूर के शहरों को भी निशाना बना सकते हैं।

कोयला मंत्रालय कल वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 13वें दौर का शुभारंभ करेगा

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 13वें दौर का शुभारंभ करने वाला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि और कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

यह आयोजन भारत के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया के प्रत्येक दौर में स्थापित और नए उद्योग जगत के दिग्गजों की मजबूत भागीदारी देखी गई है। इसका उद्देश्य कोयला उत्पादन में तेजी लाना और देश की बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आगामी 13वें दौर में खदानों की पेशकश सबसे उदार शर्तों पर जारी रहेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न हितधारकों से निवेश आकर्षित होगा।

स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 5.0 के लिए तैयारी बैठक आयोजित

(जीएनएस)।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने आज विशेष अभियान 5.0 के लिए पहली तैयारी बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की और इसमें डाक, कोयला, शिक्षा, संस्कृति आदि मंत्रालयों सहित 84 मंत्रालयों/विभागों के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेष अभियान 5.0, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करना और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है। बैठक के दौरान, डीएआरपीजी ने विशेष अभियान 5.0 के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत किए।

यह अभियान दो चरणों में लागू किया जाएगा –प्रारंभिक चरण 16 से 30 सितंबर, 2025 तक और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक। विशेष अभियान 5.0 का शुभारंभ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा सितंबर 2025 में किया जाएगा।

विशेष अभियान 5.0 मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/ अधीनस्थ/ स्वायत्त कार्यालयों, विदेशी मिशनों और केन्द्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रक्षा प्रतिष्ठानों, रेलवे/डाकघरों आदि के सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता पर केंद्रित होगा। यह अभियान संसदीय आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, मंत्रालयों के बीच के संदर्भों, पीएमओ संदर्भों और लोक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही, सीएसएमओपी 2022 के तहत अभिलेख प्रबंधन का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान की प्रगति की निगरानी स्पेशल कैंपेन डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल (एससीडीपीएम) के माध्यम से की जाएगी, जिसकी साप्ताहिक समीक्षा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी।

2021 में अपनी शुरूआत के बाद से, यह विशेष अभियान प्रतिवर्ष लागू किया गया है, जिसमें 12 लाख से अधिक कार्यालयों को शामिल किया गया है, 696.27 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त किया गया है, 137.86 लाख फाइलों का निपटान किया गया है और कबाड़ निपटान से ₹3296.71 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

शहरों में दोहरी गर्मी और अत्यधिक वर्षा का सामना करना पड़ रहा

(जीएनएस)।

सरकार आईपीई ग्लोबल और ईएसआरआई इंडिया की हालिया रिपोर्ट से अवगत है, जिसमें पाया गया है कि भारत के शहरों में 2030 तक हीटवेव के दिनों में दोगुनी वृद्धि और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि होगी। इसमें खुलासा किया गया है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन से भारत भर में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की तीव्रता में 43% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे देश अधिक गर्म और आर्द्र हो जाएगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शहरी क्षेत्रों सहित भारत के विभिन्न स्थानों पर, स्टेशन और शहर–आधारित मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके, लू और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम घटनाओं की निरंतर निगरानी करता है। इसके अलावा, आईएमडी द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रिडेड वर्षा (25 किमी रिजॉल्यूशन) और तापमान डेटा (50 किमी रिजॉल्यूशन) का भी इन चरम घटनाओं पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न उप–मंडलों में लू के दिनों की वर्षवार संख्या अनुलग्नक–1 में दी गई है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के सहयोग से, जलवायु खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों हेतु जोखिम आकलन और प्रभाव–आधारित पूर्वानुमान के लिए दृष्टिकोण प्रदान करता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को समान रूप से क्रियान्वित करता है; इसलिए, धन का आवंटन राज्यवार नहीं होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से राज्य सरकारों को सीधे धनराशि जारी नहीं की जाती है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के माध्यम से सहायता हेतु संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों की ओर से वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर विचार करती है।

राज्य सरकार, कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों की पूर्ति के अधीन, एसडीआरएफ के वार्षिक निधि आवंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण की आधिकारिक शुरूआत

भारतीय तटरक्षक बल के लिए अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण की आधिकारिक शुरूआत मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में इस्पात काटने के समारोह साथ की गई

(जीएनएस)।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित किए जा रहे छह अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों (एनजीओपीवी) की श्रृंखला में चौथे जहाज यार्ड 16404 हेतु इस्पात काटने का समारोह 20 अगस्त, 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ। स्वदेशी तकनीक से अभिकल्पित, विकसित एवं निर्मित ये 117 मीटर लंबे जहाज 23 नॉट तक की गति से चल सकते हैं और इनकी परिचालन सीमा 5,000 समुद्री मील है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस–आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव प्रणाली, रिमोट पायलटेड ड्रोन, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों से लैस अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए भारतीय तटरक्षक की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। इसमें 11 अधिकारियों और 110 कर्मियों के रहने की क्षमता भी होगी। 20 दिसंबर, 2023 को 'खरीदें (भारतीय–आईडीडीएम)' श्रेणी के तहत अनुबंधित अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महानिदेशक (तकनीकी), मुख्यालय भारतीय तटरक्षक पूर्वी समुद्र तट, महानिरीक्षक एनजी रवींद्रन ने की, जिसमें मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के कार्यकारी निदेशक (जहाज निर्माण), श्री ए. विनोद और भारतीय तटरक्षक तथा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यह पहल भारत की बढ़ती रक्षा विनिर्माण शक्ति एवं आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार के अटूट विश्वास को प्रदर्शित करती है। यह भारतीय तटरक्षक बल को राष्ट्रीय समुद्री हितों की अधिक प्रभावशीलता के साथ सुरक्षा करने के लिए सशक्त भी बनाती है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, हरियाणा सरकार को हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) विकसित करने में सहायता करेगा

हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर से 32,417 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और 1.25 लाख रोजगार सृजित होंगे

प्रविष्टि तिथिः 20 अवक्ष् 2025 6:51ढट ु८ ढक्ह ऊ्र

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास में हरियाणा सरकार का सहयोग करेगा। अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), हरियाणा सरकार और हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम (एचएडीसी) के बीच राज्य समर्थन समझौते (एसएसए) और शेयरधारक समझौते (एसएचए) पर हस्ताक्षर किए।

ये समझौते, हरियाणा में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसकी शुरूआत हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास से होगी। स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करके और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करके, एकेआईसी मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने और भारत को और अधिक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हरियाणा में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) हिसार के राज्य में आर्थिक विकास का एक प्रमुख संचालक बनने की संभावना है। इसके विकास से व्यापार–अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहन मिलेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और एक प्रमुख औद्योगिक स्थल के रूप में हरियाणा की स्थिति और मजबूत होगी। इस क्लस्टर से भारत और दुनिया भर के निवेशकों की महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित होने की संभावना है, जिससे देश के विनिर्माण क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

2,988 एकड़ में फैला आईएमसी हिसार, हरियाणा के हिसार में नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। 32,417 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता और 4,680 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ, इससे 1.25 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी के बीच रणनीतिक रूप से स्थित, यह एनएच–52, एनएच–09, रेल संपर्क और प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों के निकटता के माध्यम से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। उन्नत बुनियादी ढांचे और हिसार शहर के निकटता के साथ, यह आईएमसी हरियाणा और उत्तर भारत के औद्योगिक भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तैयार है।

इन समझौतों पर एनआईसीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, श्री रजत कुमार सैनी; हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की आयुक्त एवं सचिव, श्रीमती अमनीत पी. कुमार; और हरियाणा सरकार के एचएडीसी के प्रबंध निदेशक, श्री नरहरि सिंह बांगर ने हस्ताक्षर किए। यह भविष्य के अनुकूल सहयोग इन औद्योगिक समूहों के विकास की नींव रखता है जो अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत रणनीतिक केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे और भारत के एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के दृष्टिकोण में योगदान देंगे।

स्वदेश में डिजाइन सक्षम–3000 एक उच्च–प्रदर्शन स्विच–कम–राउटर

(जीएनएस)।

सक्षम–3000 एक उच्च–प्रदर्शन स्विच–कम–राउटर है, जिसे दूरसंचार विभाग की अनुसंधान एवं विकास शाखा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी–डॉट) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह 25.6 टेराबिट प्रति सेकंड की स्विचिंग क्षमता प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के नेटवर्क कनेक्शनों को सपोर्ट करता है। यह उपकरण मानक उपकरण रैक में फिट होने के लिए बनाया गया है और इसमें विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने वाली विशेषताएँ शामिल हैं, जैसे बैकअप पावर सप्लाई और कूलिंग फैन जिन्हें सिस्टम को बंद किए बिना बदला जा सकता है। इसे लचीलेपन के लिए डिजाइन किया गया है, जो नेटवर्क फंक्शंस और संचार विधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। ये क्षमताएँ इसे आधुनिक डिजिटल नेटवर्क में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती हैं, जहाँ उच्च प्रदर्शन, विश्वसनीयता और अनुकूलनशीलता आवश्यक है। सक्षम–3000 का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जिसमें डेटा केंद्रों में लीफ स्विच, स्पाइन स्विच या सुपर–स्पाइन स्विच के रूप में तैनाती, साथ ही दूरसंचार और आईपी नेटवर्क में एज राउटर या कोर राउटर के रूप में कार्य करना शामिल है। बड़े उद्यमों और दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा सक्षम–3000 तकनीक के व्यावसायिक उपयोग और अपनाने को सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बड़े पैमाने पर विनिर्माण और उपयोग के लिए उत्पादन तकनीक पहले ही एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) भागीदार, मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद को विभिन्न दूरसंचार उत्पाद प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जा रहा है जहाँ सी–डॉट भाग ले रहा है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

वर्तमान में भारत की जरूरतों को महसूस करता चीन

मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी की विदेश मंत्री जयशंकर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ हुईं बैठकों को सार्वजनिक भले ही नहीं किया गया किन्तु जानकारी के मुताबिक आशा के अनुरूप दोनों ही बैठक सफल रहीं। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री यी ने भारत की तीन प्रमुख चिन्ताओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। पहला भारत को उर्वरकों, दूसरा मृदा खनिजों, उच्चस्तरीय तकनीकी उत्पादों, जैसे इलेक्ट्रानिक वाहन, ड्रोन और बैटरी स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रंखला में एक प्रमुख आपूर्ति कर्ता रहा है और तीसरी चिन्ता सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को चीन पूरा करेगा। दरअसल वैश्विक मृदा खनन में चीन का लगभग 70 प्रतिशत योगदान है। चीन 2023 तक भारत को भारी मात्रा में उर्वरक आपूर्ति करता था। किन्तु उसने भारत सहित कई देशों का उर्वरक निर्यात रोक दिया था। इसी तरह उसने भारत से खनिज खोदने वाली मशीनों का निर्यात भी बंद कर दिया था। सच तो यह है कि भारत और चीन के बीच मित्रता तो है नहीं। दोनों देशों के बीच स्पष्ट और रचनात्मक संबंधों का अभाव तो रहा ही है, साथ ही लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास सीमावता क्षेत्रों में तनाव घटाने की प्रव्रिया भी 2020 से बिल्वुल स्थगित हो चुकी थी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच चार साल तक गतिरोध बना रहा किन्तु अब सीमावार्ता में तेजी आने और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली को प्रमुखता देने से लगता है कि दोनों देशों में उत्सुकता तो दिख ही रही है। असल में भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की जरूरत दोनों को है। संबंधों के बीच कई उतार-चढ़ाव आए किन्तु भारत और चीन ने अपने आयात-निर्यात पर बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लगाया था। भारत ने ही चीन के तमाम गैर जरूरी उत्पादों के आयात पर रोक लगाईं जबकि चीन ने भारत के उत्पादों के आयात पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया। 2020 में गलवान में हुए सैन्य टकराव के बाद चीन से भारत ने कच्चे माल ज्यादा आयात शुरू कर दिया। इसलिए आयात की मात्रा कम नहीं हुईं लेकिन चीन ने 2023 में उर्वरक, दुर्लभ मृदा खनिजों और सुरंग खोदने की मशीनें देना बंद कर दी तब भारत के लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो गईं। कदाचित भारत इन तीनों ही वस्तुओं की आपूर्ति किसी और देश से करवाने का प्रयास कर सकता था किन्तु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भारत के खिलाफ टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल किया उससे भारत ने खुद को ब्रिक्स और रिक यानि रूस, भारत व चीन की तिकड़ी के साथ खड़ा होना वूटनीतिक मजबूरी माना। विदेश मंत्री यी की विदेश मंत्री जयशंकर के बीच हुईं वार्ता के बाद चीन ने जिस तरह भारत की जरूरतों को महसूस किया है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गईं है कि भारत अब आंख मूंद कर अमेरिका के साथ नहीं रहेगा। भारत मानता है कि हमारी समझदारी इसी में है कि हम किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहते हुए सभी देशों से संबंध बनाएं और निभाएं। किसी के साथ संबंधों की कीमत पर उसकी दुश्मनी के सहयोगी न बनें। अमेरिका भले ही लोकतांत्रिक देश है किन्तु वह कई दशकों तक भारत के भरोसे और विश्वास से वंचित रहा है। बड़ी मुश्किल से पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिटन के कार्यर्काल में अपनी तमाम परम्परागत नीतियों को छोड़कर भारत के भरोसे और विश्वास को हासिल करने के लिए अमेरिका ने प्रयास किया। उसे बहुत हद तक सफलता भी मिली थी किन्तु ट्रंप ने एक ही झटके में भारत को एक बार फिर अपने से दूर करने पर विवश कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री यी की मंगलवा को हुईं मुलाकात और प्रधानमंत्री की एससीओ बैठक में शामिल होना तथा राष्ट्रपति शी जिन पिग से मिलने की योजना और मंगलवार को ही विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा रूस की तीन दिवसीय यात्रा यानि भारत की रिक संबंधों को लेकर धुआंधार सव्रिय वूटनीति का सटीक संदेश यह है कि भारत अमेरिका से उतनी ही मित्रता रखेगा, जितनी कि नईं दिल्ली को जरूरत है मतलब यह कि भारत अब अमेरिका की समस्याओं की गठरी ढोने वाला नहीं है। यही नहीं अमेरिका को स्पष्ट संदेश है कि भारत अब रूस और चीन से अपने संबंधों को लेकर किसी तरह संकोच करने वाला नहीं है।

भारतीय डाक प्रणाली का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 अनुप्रयोगों, बुद्धिमान प्लेटफार्मों और परस्पर जुड़े इकोसिस्टम को जोड़ती है

डीओपी आईटी 2.0 परियोजना के अंतर्गत, विभाग ने आधुनिक डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) नामक नए आंतरिक रूप से विकसित डाक और लॉजिस्टिक समाधान का कार्यान्वयन पूरा कर लिया है

(जीएनएस)।

डाक विभाग ने आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 (डीओपी आईटी 1.0) को लागू किया, जो एक मिशन मोड ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य विभाग को ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए एक प्रौद्योगिकी संचालित संगठन में बदलना है।

डीओपी आईटी 1.0 परियोजना की प्रगति और चुनौतियों के आकलन के लिए, परियोजना की मध्यावधि समीक्षा 2018 में आईआईएम, लखनऊ द्वारा की गई थी और परियोजना का अंतिम मूल्यांकन 2021 में एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ता, आईआईपीए (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान) द्वारा किया गया था। अंतिम मूल्यांकन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं -

आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के कार्यान्वयन के बाद विभाग ने 6.33 प्रतिशत की आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) हासिल की।

डाक विभाग की 'आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012' द्वारा किए गए गुणात्मक और मात्रात्मक योगदान प्रभावी पाए गए हैं। गुणात्मक रूप से, सेवाओं की तीव्र डिलीवरी को प्रमुख सुधारों में से एक माना गया है। मात्रात्मक रूप से, सुलभ डाक सेवाओं की संख्या, विशेष रूप से बैंकिंग सेवाओं से वंचित/अल्प-बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए, बढ़ी है।

डाक परिचालन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुशलतापूर्वक कार्य करता पाया गया है।

सर्वेक्षणों के अनुसार, डाक विभाग (डीओपी) के ग्राहक डाक कर्मचारियों से कुल मिलाकर संतुष्ट पाए गए। नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण आई तकनीकी खराबी से कुछ ग्राहक निराश हुए।

डीओपी आईटी 1.0 के क्रम में, सरकार ने 2022-23 से शुरू होने वाली आठ वर्षों की अवधि के लिए 5785 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (डीओपी आईटी 2.0) को मंजूरी दी है।

सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 अनुप्रयोगों, बुद्धिमान प्लेटफार्मों और आपस में जुड़े इकोसिस्टम को जोड़ती है ताकि विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से अपने हितधारकों को डाक और वित्तीय सेवाओं का एक समावेशी, एकीकृत और एकल-खिड़की दृश्य प्रदान किया जा सके।

डीओपी आईटी 2.0 परियोजना के अंतर्गत, विभाग ने देश के सभी 1.64 लाख डाकघरों में आधुनिक डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) नामक नए आंतरिक रूप से विकसित डाक और लाजिस्टिक समाधान की शुरूआत पूरी कर ली है। यह डाक सेवाओं को तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएगा और डाकघरों को क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा।

डाक विभाग ने ग्रामीण जनता तक डाक, वित्त, बीमा और सरकारी सेवाएँ पहुँचाने के लिए देश के सभी ग्रामीण शाखा डाकघरों को एंड्रॉइड आधारित मोबाइल फोन उपलब्ध कराए हैं। एपीटी के अंतर्गत आंतरिक रूप से विकसित आंतरिक मोबाइल ऐप (आईएमए) अब इन फोनों में उपलब्ध है, जिसमें प्राप्तकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर लेना, वस्तुओं की डिलीवरी के लिए रीयल-टाइम अपडेट और एकीकृत डिजिटल भुगतान सुविधा (डायनेमिक क्यूआर कोड कार्यक्षमता का उपयोग करके) की क्षमता है।

इसके अलावा, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी), डाक और पार्सल सेवाओं के क्षेत्र में पूरे देश में, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित, विभाग द्वारा की गई पहलों की सूची, वितरण अंतराल को कम करने, बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय डाक प्रणाली के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।

अनुबंध-I

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में पहल

ऑटोमेटिक टैलर मशीन (एटीएम) सुविधाएं

इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग।

डाकघर से बैंक और इसके विपरीत धन हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण (एनईएफटी) / रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सेवाएं।

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) सुविधा - बैंक खातों में ब्याज और परिपक्वता राशि जमा करने के लिए

शेष राशि और मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए ई-पासबुक सुविधा।

सभी प्रकार के डिजिटल लेनदेन के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक-डाकघर बचत खाता लिंकेज सेवाएं।

इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) सुविधा।

भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) में पहल

रीयल-टाइम डेटा साझाकरण

(जीएनएस)।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों और राज्य सरकारों के बीच डेटा साझा करने के लिए रीयल-टाइम संचार चैनल मौजूद हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आईएमडी और एनसीएस-एमओईएस क्रमशः इसरो, एनडीएमए और राज्यों के साथ चौबीसों घंटो के आधार पर रीयल-टाइम मौसम संबंधी और भूकंप संबंधी डेटा साझा करते हैं। आईएमडी द्वारा आपदाओं से संबंधित जानकारी, इसमें अवलोकन, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ शामिल हैं, जिला स्तर तक एपीआई, सीएपी, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप और सीधे प्रसारित की जाती है। आईएनसीओआईएस समुद्री घटनाओं जैसे सुनामी और उससे जुड़ी तूफानी लहरों, ऊँची लहरों आदि के लिए बहु-खतरे वाली प्रारंभिक चेतावनियाँ प्रदान करता है। आईएनसीओआईएस, आईएमडी के साथ समन्वय में, चक्रवातों के दौरान आँकड़ों का आदान-प्रदान और संयुक्त बुलेटिन भी जारी करता है। चेतावनियाँ एनडीएमए और राज्य सरकारों के साथ कई माध्यमों, मौसम और समुद्र ऐप के माध्यम से साझा की जाती हैं, जिनमें एनडीएमए का सीएपी-आधारित सचेत सिस्टम भी शामिल है। एनसीएस चौबीसों घंटे राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क का संचालन करता है, भूकंपों का पता लगाता है और भूकंप के मापदंडों का अनुमान लगाता है और एकीकृत प्रसार प्रणाली (यूडीएस) का उपयोग करके आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ मापदंडों को साझा करता है। इसमें भूकम्प ऐप के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के साथ वास्तविक समय में साझा करना भी शामिल है।

एनडीएमए और बीआईएस ने अपर्याप्त इमारतों और संरचनाओं के भूकंपीय रेट्रोफिटिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। भूकंप जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे जीवन रक्षक भवनों के सुरक्षा ऑडिट और रेट्रोफिटिंग पर बल देता है। हालाँकि दिशानिर्देश और बजट आवंटन मौजूद हैं, लेकिन कार्यान्वयन की गति सीमित वित्तीय संसाधनों, तकनीकी विशेषज्ञता में कमी, कुछ स्तरों पर कम प्राथमिकता और अपर्याप्त सार्वजनिक एवं संस्थागत जागरूकता जैसे कारकों से बाधित रही है। हालाँकि इन चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास जारी हैं और बेहतर क्षमता निर्माण, बेहतर समन्वय और इस मुद्दे पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

आईएनसीओआईएस समुद्री जानकारी और बहु-खतरे की पूर्व चेतावनी सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें सुनामी, तूफानी लहरें, ऊँची लहरें, उफान और चरम समुद्री परिस्थितियों में तेज समुद्री धाराओं के लिए अलर्ट और एसएमएस, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, सचेत प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लिकेशन आदि सहित कई संचार माध्यमों के माध्यम से हितधारकों को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिशानिर्देश (डीआरआर-2016 पर प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा) देश में भूभौतिकीय और जल-मौसम विज्ञान और क्रायोस्फेरिक (जीएलओएफ) आपदा घटनाओं के लिए आपदा-संबंधी तैयारियों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को तकनीकी और वैज्ञानिक फीडबैक के लिए आईएमडी, एनसीएस, आईएनसीओआईएस, एनसीसीआर, एनसीपीओआर और इसरो को शामिल करके खतरा मानचित्रण, नियमित अभ्यास और जागरूकता अभियानों के माध्यम से नियमित सार्वजनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। एनडीएमए सभी आयु वर्गों को शामिल करते हुए देशव्यापी अभ्यास आयोजित करता है। इसके पूरक के रूप में जमीनी स्तर के समुदायों तक पहुंचने के लिए टीवी और रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भूकंप, सुनामी और मौसम संबंधी चेतावनियों सहित आपदा संबंधी जानकारी संस्थागत वेबसाइटों, मोबाइल ऐप, एसएमएस अलर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

एनसीएस और आईएनसीओआईएस, एनडीएमए, स्कूलों, एसडीएमए और एनआईडीएम के साथ-साथ तटीय राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वार्षिक मॉक ड्रिल के माध्यम से भूकंप और सुनामी की तैयारियों को मजबूत करते हैं ताकि पहले प्रतिक्रियाकर्ता या जमीनी स्तर तक पहुँच बनाई जा सके। यह भारत में यूनेस्को-आईओसी "सुनामी तैयारी" कार्यक्रम का भी नेतृत्व करता है, जिसके तहत ओडिशा के 26 तटीय गाँवों को मान्यता मिली है, जो तटीय लचीलापन बनाने में महत्वपूर्ण है।

आईएनसीओआईएस को यूनेस्को-आईओसी के सुनामी चेतावनी नेटवर्क द्वारा सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है और समुद्री खतरों की चेतावनी और क्षमता निर्माण के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय-एनओएए साझेदारी के माध्यम से, भारत समुद्र विज्ञान संबंधी डेटा साझाकरण और संयुक्त अनुसंधान में संलग्न है, जबकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वैश्विक भूकंपीय डेटा सहयोग को भी मजबूत करता है। एनसीएस डेटा साझा करने के लिए वैश्विक भूकंपीय नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय आयोग (आईएससी), रूस और जापान और ताइवान की अन्य एजेंसियों और आईएनसीओआईएस के साथ काम करता है।

लद्दाख में अंतरिक्ष परियोजनाएं

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश में सुदूर संवेदन प्रेक्षणों में सुधार लाने के लिए 2027-2028 तक रिसोर्ससैट-3 व 3ए, रिसोर्ससैट-3एस और 3एसए, एचआरएसएटी, जी20 उपग्रह तथा तृष्णा उपग्रह का निर्माण कर रहा है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी लाभ होगा। कक्षा में स्थित भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों (काटोसैट-2 श्रृंखला, काटोसैट-3, रिसोर्ससैट-2 एवं 2ए, रीसैट-1ए, इनसैट-3डीआर एवं 3डीएस, ओशनसैट-3, सरल और निसार) से प्राप्त आंकड़े भी भारत में उपलब्ध हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी शामिल है।

परिचालन संचार उपग्रहों में से 12 उपग्रहों की कवरेज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक है। यह क्षमता दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 10 विदेशी उपग्रहों और 3 निम्न पृथ्वी कक्षा/मध्यम पृथ्वी कक्षा तारामंडलों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित भारत में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण दिया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग के प्राकृतिक संसाधन गणना कार्यक्रम (एनआर सेंसस) के एक भाग के रूप में हिमालय और लद्दाख सहित राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों, भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण तथा बंजर भूमि की स्थिति की आवधिक निगरानी की जाती है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग ने हिमालयी संसाधनों, प्राकृतिक खतरों और भू-गतिकी की निगरानी के लिए "उत्तर-पश्चिम हिमालय (लद्दाख सहित) का पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन" किया है।

इसरो/अंतरिक्ष विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निम्नलिखित सुदूर संवेदन अनुप्रयोग परियोजनाएं भी शुरू की हैं:

लद्दाख विशिष्ट मॉडलिंग और अंतरिक्ष अनुप्रयोग (एलएएमए): लद्दाख क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की वैज्ञानिक जांच। प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए एक अनुकूलित गतिशील जियोपोर्टल विकसित किया गया।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए संबद्ध डेटाबेस के साथ स्थानिक डेटा अवसंरचना (एसडीआई) जियोपोर्टल (जियो-लद्दाख): जैव-संसाधन विस्तार, कृषि और बागवानी प्रबंधन, कृत्रिम ग्लेशियरों के विकास के लिए स्थल, जल संसाधनों का संरक्षण, सौर एवं पवन ऊर्जा का संचयन, बाढ़ के खतरे का आकलन आदि।

अमृत-1.0: लेह और करगिल शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के अति उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह डेटा निर्माण का उपयोग करके बड़े पैमाने पर शहरी भू-स्थानिक डेटाबेस बनाया गया।

अमृत-2.0: लेह और करगिल शहरों के लिए जल निकाय सूचना प्रणाली का विकास।

एलयूएलसी परिवर्तन विश्लेषण: लद्दाख के लिए 2020-21 और 2025-26 के 1:50,000 पैमाने पर भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन विश्लेषण का आकलन।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग का आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम (डीएमएसपी) लद्दाख के हिमालयी क्षेत्र सहित राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं हेतु नोडल मंत्रालयों/विभागों को उपग्रह डेटा-आधारित इनपुट प्रदान करता है।

कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट

(जीएनएस)।

कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट पर बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान स्थिति, इसके पूर्ण कमीशनिंग की समय-सीमा और अब तक परियोजना के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई धनराशि सहित:

ईस्ट-कोस्ट रोड के मार्ग परिवर्तन के लिए भूमि को छोड़कर भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

साइट विकास कार्य पूरा हो गया है और तकनीकी सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

विभिन्न कार्य केन्द्रों पर विभिन्न उपकरणों और संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट को वित्त वर्ष 2026-27 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट को आवंटित धनराशि झ 985.96 करोड़ रुपये।

परियोजना के लिए उपयोग की गई धनराशि झ 389.58 करोड़ रुपये (31 जुलाई 2025 तक)

पेलोड क्षमता के संदर्भ में कुलसेकरपट्टिनम प्रक्षेपण स्थल के विशिष्ट लाभ और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसएचएआर (एस डी एस सी-एस एच ए आर) में मौजूदा प्रक्षेपण सुविधा के साथ इसकी तुलना निम्नानुसार है:

कुलसेकरपट्टिनम प्रक्षेपण स्थल इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) श्रेणी के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता को बढ़ाएगा और साथ ही उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करेगा।

एसडीएससी शार, श्रीहरिकोटा से कार्यात्मक रूप से असाधारण सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं (एसएसपीओ) के प्रक्षेपण के लिए भूमि पर खर्च किए गए चरणों के प्रभाव से बचने हेतु रॉकेट को गतिशील करने की आवश्यकता होती है और इससे पेलोड क्षमता में काफी कमी आएगी।

कुलसेकरपट्टिनम से प्रक्षेपण के समय एसएसएलवी से एसएसपीओ तक की पेलोड क्षमता लगभग 300 किलोग्राम है, जबकि एसडीएससी शार से प्रक्षेपण के समय उपयोगी पेलोड के लिए यह क्षमता अपर्याप्त है।

कमीशनिंग के बाद, गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) द्वारा एसएसएलवी और समकक्ष प्रक्षेपण यानों का प्रक्षेपण कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट से किए जाने की योजना है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।

परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन

(जीएनएस)।

वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट तक नियोजित विस्तार से उत्पन्न होने वाले परमाणु अपशिष्ट का प्रबंधन वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति के अनुरूप है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और ईंधन चक्र सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले परमाणु अपशिष्टों का निपटान/प्रबंधन "परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962", उसके बाद के संशोधनों और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित रूप से किया जाता है।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रबंधन की परिचालन क्षमता और इसके अवलोकन के लिए स्वतंत्र नियामक क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन स्थापित किया गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में संचालन के दौरान उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट निम्न और मध्यम गतिविधि स्तर के होते हैं और उनका प्रबंधन स्थल पर ही किया जाता है। इन अपशिष्टों को उपचारित, सांद्रित, संहत, सीमेंट जैसी ठोस सामग्रियों में स्थिर किया जाता है और विशेष रूप से निर्मित संरचनाओं जैसे प्रबलित कंक्रीट खाइयों और टाइल के छिद्रों के माध्यम से इनका निपटारा किया जाता है। अपशिष्ट में मौजूद रेडियोधर्मिता के प्रभावी परिसीमन की पुष्टि करने के लिए भूमिगत जल और मिट्टी के नमूनों की नियमित निगरानी करके योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए बोर-वेल की मदद से निपटान सुविधाओं पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अनुरूप है।

वर्ष 2025-26 के बजट घोषणा के बाद वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समिति द्वारा सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया गया है, जिसमें परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं की समीक्षा की गई है। परमाणु ऊर्जा मिशन की सफलता के लिए 5 से 7 वर्ष की समय-सीमा के भीतर, नीतिगत, कानूनी और विनियामक सुधारों की दिशा में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के सभी संबंधित क्षेत्रों में प्रयुक्त ईंधन पुनसंर्साधन और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अनेक गतिविधियां शामिल हैं।

आमतौर पर, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी ठोस अपशिष्ट का निपटारा संयंत्रों के बंद होने सहित उनके संचालन तक घन मीटर/वर्ष/मेगावाट के भीतर ही किया जाता है। अपशिष्ट के निपटारे की मात्रा और स्थान के संबंध में रेडियोधर्मी अपशिष्टों का रिकॉर्ड नियमित रूप से नियामक प्राधिकरण के पास दर्ज किया जाता है। देश में विखंडनीय सामग्री की प्राप्ति और परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के बोझ को कम करने के लिए एक बंद परमाणु ईंधन चक्र का पालन किया जाता है, जहां खर्च किए गए ईंधन को पुनः संसाधित किया जाता है और इसके अधिकांश घटकों को भविष्य के रिएक्टरों के लिए ईंधन के रूप में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। पुनः प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न उच्च-स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट को विट्रीफिकेशन द्वारा एक निष्क्रिय ग्लास मैट्रिक्स में स्थिर किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप अंतरिम भंडारण के लिए ठोस भंडारण निगरानी सुविधाओं में संग्रहीत किया जाता है। अपशिष्ट मात्रा में कमी के लिए सामाजिक अनुप्रयोग के लिए लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी घटकों की प्राप्ति और उपयोगी रेडियोआइसोटोप के पृथक्करण/निष्कर्षण के लिए विभाजन प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास जारी है और निष्क्रिय या अल्पकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्टों के लिए लंबे समय तक रहने वाले एक्टिनाइड्स का निपटारा करने से आने वाले दशकों में दीर्घकालिक निपटान की आवश्यकता समाप्त होने की संभावना है।

बजट 2025-26 के दौरान घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य एसएमआर के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का परिव्यय बनाना है जो अनुसंधान और विकास के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करेगा। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट के मिशन और संबंधित ईंधन चक्र गतिविधियों (परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है) को इसके कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी जिसे अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के साथ-साथ निजी वित्तपोषण द्वारा पूरा किया जाएगा।

किसानों को वाई-फाई सुविधा का लाभ

(जीएनएस)।

आरजीआई (भारत के महापंजीयक) के आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 30.06.2025 तक 6,26,055 गांवों में मोबाइल कवरेज नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सुविधा (3जी/4जी) उपलब्ध है।

देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट के माध्यम से देश में कुल 13,01,193 एफटीटीएच कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। वाई-फाई तकनीक से युक्त एफटीटीएच कनेक्शन का उपयोग सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं जैसे ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स आदि तक पहुँचने के लिए किया जा रहा है, जिसमें किसानों द्वारा कृषि के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने और कृषि में नए विकास के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत 4जी संतृप्ति परियोजना, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)- बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट(बीआईपी) परियोजना, भारतनेट परियोजना आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएँ गाँवों में मोबाइल कवरेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की जा रही हैं। 4जी संतृप्ति परियोजना के अंतर्गत जून 2025 तक, देश भर में विभिन्न सरकारी वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत 21,748 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए "पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23" नामक एक पुनर्निर्धारित और विस्तारित योजना शुरू की है। राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2022-23 के भाग-श (ऑप्टिकल फाइबर केबल) के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग वर्तमान में कवर की गई ग्राम पंचायतों से लेकर गाँवों तक भारतनेट का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है, ताकि ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) पर सरकारी संस्थानों (जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन, कृषि विकास केन्द्र, डाकघर, राशन की दुकान आदि), निजी संस्थानों और घरों को भारतनेट नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएमवाणी) के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार हेतु दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, देश भर में 3,53,105 पीएमवाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित हैं।

यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

रामजन्मभूमि केस के अहम गवाह से मिले श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार, अब होगा मंदिर निर्माण का सपना साकार

-वृंदावन प्रवास पर आए श्री चित्रकूट तुलसीपीठाधीश्वर रामभद्राचार्य से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप की हुई वार्ता

मथुरा (जीएनएस)। श्रीराम जन्मभूमि केस में अहम गवाह रहे श्रीचित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानन्दाचार्य जी महाराज ने भारत समेत करीब एक दर्जन से भी ज्यादा देशों में अभी तक भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने को आंदोलन खड़ा कर चुके श्रीकृष्ण के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट को आश्वस्त किया है कि जहां कहीं भी उनकी आवश्यकता होगी, वह वहीं खड़े नजर आएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के उस हिस्से पर मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, जिस स्थान पर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, तब तक आंदोलन को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना है। न्यास के अध्यक्ष ने भी महाराजश्री के साथ आंदोलन की रणनीति साझा की और कहा कि हमारी विजय होगी। श्रीराम जन्मभूमि केस में अहम गवाह रहे और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार के बीच वृंदावन में हुई विशेष वार्ता के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले चल रहे आंदोलन से अधिक से हिंदुओं को जोड़ने की रूपरेखा तय करने जुट गया है। न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों महाराजश्री वृंदावन में ही प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को विभिन्न स्तरों पर चल रहे

आंदोलन की जानकारी महाराजश्री को विस्तार से दी। उन्होंने पूर्व में इस मुद्दों पर पहले भी दो बार जगद्गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज से बातचीत हो चुकी हैं, लेकिन हाल ही में कुछ नए पेंच भी सामने आए थे, उन पर महाराजश्री से लम्बी और गंभीर चर्चा की। इस दौरान महाराजश्री ने कई सुझाव भी दिए और कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए जारी न्यास के आंदोलन से अधिक से अधिक हिंदू समाज को जोड़ा जाए। हिंदुओं के बीच जाकर उनको जागरूक भी किया जाए और उनको श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के तोड़े जाने का इतिहास भी स्मरण कराया जाए। इस पर महेंद्र प्रताप सिंह ने उनको बताया कि हिन्दू चेतना यात्रा और चलो गांव की और यात्राएं देश के अलग-अलग हिस्सों में जारी है तथा लोग आंदोलन से जुड़ भी रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने महाराजश्री को बताया कि अब इस मामले में आगामी 22 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कहा है हमने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने की ठोस तैयारी की है। इस मौके पर वार्ता के दौरान संत रामचन्द्रदास, वृंदावन के संत श्यामसुंदर बृजवासी महाराज और पंडित श्यामानंद महाराज आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस ने वोट चोरी के विरोध में निकाला मशाल जुलूस : जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने लगाया मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप

मथुरा (जीएनएस)। मांट विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी और चुनावी में धांधली के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस जेएसएम स्कूल से मांट थाने तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता, किसान, युवा और स्थानीय लोग मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। इस बीच पूरे रास्ते में वोट की चोरी बंद करो, लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही नहीं चलेगी, जैसे नारे गूंजते रहे। इस बीच कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि मताधिकार हर नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। यदि चुनाव प्रक्रिया में धांधली और वोट चोरी होती है तो यह सीधे लोकतंत्र पर कुठाराघात है। कहा कि वर्तमान सरकार गरीब, किसान और मजदूर वर्ग की अनदेखा करके केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। कहा कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है और कांग्रेस इस अन्याय को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री धनगर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन और सरकार ने वोट चोरी की घटनाओं की निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। इस दौरान जुलूस शांतिपूर्ण रहा लेकिन साथ ही उत्साह और आक्रोश से भरा हुआ था। मशालों की रोशनी और नारों की गूंज ने पूरे मांट क्षेत्र का माहौल गरमा दिया। इस दौरान आस-पास गांवों के लोग भी इस विरोध को देखने पहुंचे। इस बीच राहगीर और दुकानदार भी चर्चा में शामिल हुए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मताधिकार सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कई युवाओं ने इसे लोकतंत्र बचाने की निर्णायक लड़ाई करार दिया है। इस दौरान मशाल जुलूस में पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि, डा. आशुतोष भारद्वाज, रूपा लवानियां, करण निषाद, हरिओम उपाध्याय, ब्लॉक अध्यक्ष हरदेव सिंह, सतीश शर्मा, रिंकू चौधरी, गंगा शरण दीक्षित, अशोक शर्मा, खचेरमल प्रधान, कुबेर दत्त, बाबूलाल, चंद्रमोहन, राजू तिवारी, दिलशाद खांन, विनोद निषाद और अवधेश चौधरी समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

अग्रसेन महोत्सव के लिए सौंपी गई जिम्मेदारी : रजत वर्ष में भव्य होगा अग्रसेन मेला

मथुरा (जीएनएस)। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर श्री अग्रवाल सभा की बैठक अग्र वाटिका में आयोजित हुई। बैठक में कार्यक्रम से संबंधित संयोजक घोषित करते हुए विस्तृत चर्चा की गई। जयंती महोत्सव के संबंध में मुख्य मीडिया प्रभारी सचिन अग्रवाल घी वालों ने बताया कि मुख्य मेला संयोजक का प्रभार अनुराग सिंघल बरौली वाले और मुख्य जयंती संयोजक प्रदीप अग्रवाल पोशाक वालों को दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा गौरांग सिंघल कारे बनिया, शोभायात्रा संयोजक, चिराग अग्रवाल सर्राफ, पुष्पांजलि संयोजक, योगेश गोयल वृक्षारोपण संयोजक, अतुल अग्रवाल शोरा वाले मुख्य चंदा संयोजक और विजय गोयल औषधालयद्ध पुस्तिका संपादक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सह मीडिया प्रभारी जगत बहादुर अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष अग्रसेन मेला के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कहा कि आगामी 24-25 और 26 सितंबर को बीएसए डिग्री कॉलेज मैदान में अग्रसेन मेला आयोजित किया जाएगा। अग्रसेन शोभायात्रा 23 सितम्बर को शाम 4 बजे भरतपुरगेट से प्रारंभ होगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अशोक बसंल सर्राफ ने सात दिवसीय अग्रसेन महोत्सव के प्रत्येक कार्यक्रम में सभी बंधुओं की सहभागिता का आ'ान किया, ताकि अग्रवाल समाज की एकजुटता प्रदर्शित हो सके। इसीक्रम में अग्रवाल सभा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयंती प्रसाद अग्रवाल ने अग्रसेन जयंती महोत्सव में पूरी शक्ति के साथ जुटने का आ'ान किया। उन्होंने 25 वर्ष पूर्व मेला प्रारंभ करने में अहम भूमिका निभाने वालों का सम्मान करने का सुझाव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। वहीं रामलीला सभा के प्रधानमंत्री मूलचंद्र गर्ग, प्रेमजी अग्रवाल और महावीर मित्तल ने कहा कि अग्रवाल समाज में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना अग्रसेन मेला का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ महिला समिति संयोजिका आशा अग्रवाल और मीरा अग्रवाल ने बताया कि मेले का मुख्य आकर्षण 25 साल का सफर होगा। इसके अलावा "बेटी भटक मत जाना" कार्यक्रम से समाज को संदेश दिया जाएगा। बताया कि समाज की महिलाओं द्वारा कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मौके पर सभा के मंत्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल सिक्का ने बैठक का संचालन किया। बैठक में प्रमुख रूप से तिलकद्वार धर्मशाला समिति के अध्यक्ष हरीओम अग्रवाल, मंत्री कृष्ण मुरारी, महेश चंद्र अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल, सुरेश चन्द्र अग्रवाल, श्रीमती शशि अग्रवाल, मंत्री जागृति अग्रवाल, धीरज गोयल, विजय गोयल, शंकरलाल अग्रवाल सर्राफ, किशोर मित्तल, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, राजू हाथी वाले, विभोर अग्रवाल, योगेन्द्र अग्रवाल प्रेस वाले, योगेश कुमार बंसल कागजी, अतुल अग्रवाल, संदीप अग्रवाल अडूकी वाले, दीपक गर्ग आढ़ती, मनीष कुमार चौधरी, राधारमन अग्रवाल, मुकेश गर्ग कोसी, शिवकुमार अग्रवाल, मनोज कुमार अग्रवाल, अशीष गर्ग, पंकज गर्ग प्रेस वाले, पराग अग्रवाल, रवि अग्रवाल कैटर्स, अतुल अग्रवाल शोरा वाले, अमन अग्रवाल और रजनीश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

धृतराष्ट्र बन चुकी है पुलिस : खुलेआम बेखौफ होकर नशा बेच रहे तस्कर, अधीनस्थ ही कर रहे अपने कमांडर के आदेशों की अवेहलना

मथुरा (जीएनएस)। जनपद में पुलिस की कमान बेशक तेजतर्रार आईपीएस श्लोक कुमार के हाथों में है लेकिन एसएसपी के अधीनस्थ ही अपने कमांडर और सरकार की मंशा के विपरीत जाकर अवैध कार्य करा रहे हैं। एक ओर जहां देश के गृहमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों पर प्रभावी अंकुश लगाकर नशे के काले कारोबार को बंद कराने के लिए देश एवं प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर जनपद में स्मैक तस्करों के हौंसले बुलंद हैं। स्मैक तस्कर बेखौफ होकर युवा पीढ़ी को स्मैक परोस रहे हैं, जिससे स्मैक का नशा युवा पीढ़ी को धीमे-धीमे मौत के करीब ले जा रहा है। स्मैक तस्करों और पुलिस की जुगलबंदी के कारण पुलिस के बड़े अफसर भी फेल होते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संबंधित थाने की पुलिस को स्मैक तस्करों के बारे में जानकारी नहीं है, खबर तो सबकुछ है लेकिन महीने पर आने वाली नोटो की गड्डी के वजन में थाना प्रभारियों का ईमान दब चुका है। इस समय महानगर का थाना जैंत क्षेत्र स्मैक तस्करों का प्रमुख गढ़ बन चुका है। थाना जैंत के छटीकरा में सुबह और शाम को स्मैक तस्करों की मंडी सजती है। छटीकरा में लाइन लगकर स्मैक तस्कर सरेआम तस्करी कर रहे हैं लेकिन जैंत पुलिस वर्तमान में धृतराष्ट्र बन चुकी है। सबकुछ पता होने के बाद भी जैंत पुलिस की चुप्पी भ्रष्टाचार और रिश्वत के खेल की कलई खोल रही है। बता दें कि तत्कालीन एसएसपी शैलेश पांडेय के निर्देश पर तत्कालीन एएसपी आईपीएस कुंवर आकाश सिंह ने एसओजी टीम और इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को भेजकर छटीकरा में दबिश डलवाई थी। उस दौरान एसओजी टीम और इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह की टीम ने 7 स्मैक तस्करों को रंगेहाथ दबोचा था और स्मैक बरामद हुई थी। उस समय एएसपी कुंवर आकाश सिंह ने पकड़े गए स्मैक तस्करों से खुद पूछताछ की थी। इसके बाद तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेजा गया था, जबकि फुटकर में स्मैक बेचने वालों को बड़े स्तर पर तस्करी करने वाले दो तस्करों को पुलिस ने एफआईआर में फरार दशार्या था। किंतु इसके कुछ समय बाद एएसपी कुंवर आकाश सिंह को शासन ने एसपी ग्रामीण मुरादाबाद बना दिया था, इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में फरार नामजद स्मैक के बड़े तस्करों को गिरफ्तार तक नहीं किया था।

राया पुलिस ने दबोचा एक बदमाश : चोरी की अपाचे और गांजा बरामद

मथुरा (जीएनएस)। थाना राया क्षेत्र स्थित बरेली हाईवे के पास से पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शातिर के कब्जे से चोरी की बाइक और गांजा बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी राया अजय कौशल और एसआई महेन्द्र सिंह भदौरिया पुलिस टीम के साथ संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि बरेली हाईवे के निकट ककरेटिया नहर के पास एक बदमाश खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय कौशल और एसआई महेन्द्र सिंह भदौरिया पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे शातिर बदमाश नितिन पुत्र शिशुपाल

निवासी शम्भू नगर नारायच थाना एत्माद्दौला जिला आगरा को घेरकर दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए शातिर के कब्जे से चोरी की अपाचे बाइक और 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

मकान का ताला तोड़ भूमाफियाओं ने डाला अपना ताला

-मामले में तीन बार दिया जा चुका प्रार्थना पत्र, सुनवाई नहीं हुई

(जीएनएस)।

फतेहपुर। खागा कोतवाली के गनेशदासपुर गांव में भूमाफियाओं ने एक मकान का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया है। मामले में पीड़ित के भाई ने एडीएम, थाना दिवस सहित उच्चाधिकारियों को वह तीन-तीन बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है।

गनेशदासपुर गांव निवासी शिवशंकर मौर्य ने समाधान दिवस में बताया कि भाई अवधेश मौर्य व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहते हैं। गांव स्थित गाटा संख्या 42/1.3330 हेक्टेयर भूमि है, इसमें गांव का एक व्यक्ति चौथाई भाग का काश्तकार था। उपजिलाधिकारी खागा न्यायालय द्वारा जमीन का सरकारी बंटवारा करके उक्त युवक को चौथाई भाग दे दिया गया था। 19 मई 2012 भाई अवधेश मौर्य को 7 बिस्वा 2 कसी का बैनामा करके कब्जा दखल उक्त युवक ने दे दिया तथा स्वयं 6595 फिट स्टाम्प पर समक्ष गवाहान के सामने लिखकर नोटरी मजिस्ट्रेट से पंजीकृत करा दिया था, जिसका नामांतरण आदेश भी भाई के पक्ष में उक्त युवक के रजामंदी से हो गया था। 2022 में सड़क की ओर भाई ने 6510 भाग पर निर्माण कराकर उसमें गेट लगवा दिया था। उक्त युवक ने भाई की जमीन हड़पने की नियत से खागा कोतवाली और सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के भूमाफियां से सांठगांठ करके अनाधिकृत तरीके से भाई के आधे मकान की फोटो लगाकर 3 सितंबर को बेंच डाला। आरोप हैकि मामले में उन्होंने कई इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। दिनांक 12 जुलाई को अपने प्लाट के सामने सबमर्सिबल बोर कराने के लिए गड्ढा खोद रहा था, जिसमें उक्त भूमाफियाओं ने जबरन रोकवा दिया। प्रार्थी अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।

कलर्स का 'पति पत्नी और पंगा' हकीकत को पलटने आया–पति सहेंगे लेबर पेन, और होगा एक खास एआई शादी का जश्न

इस हफ्ते, कलर्स का 'पति पत्नी और पंगा – जोडियों का रियलिटी चेक' दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है हंसी, हैरानी और इमोशन से भरपूर डिनरटेनमेंट का ऐसा तड़का, जिसे देखकर सबका पेट भर जाएगा।

होस्ट सोनाली बेंद्रे शो की शुरूआत एक ऐसे चैलेंज से करती हैं जो पावर बैलेंस को तुरंत बदल देता है—एक दिन के लिए पति बनेंगे बॉस, और पत्नियों को करना होगा वही जो वे कहें। सेट पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, चेहरों पर मुस्कान फैल जाती है, और सबसे ज्यादा इस मौके का मजा उठाते हैं गुरमीत चौधरी, जिनका एक पुराना (और थोड़ा खतरनाक) सपना आखिरकार पूरा होता है—पत्नी देबिना के नाखून काटना! दर्शकों की हंसी फूट पड़ती है, लेकिन देबिना के चेहरे पर सदमे के भाव साफ नजर आते हैं। दो साल से संभालकर बढ़ाए गए नाखून, एक झटके में कट जाते

हैं—ये नजारा हर महिला को चुभ जाएगा।

लेकिन जो पति सोच रहे थे कि उनका दिन आराम से बीतेगा, वे भारी भूल कर रहे थे। पलटवार के तौर पर पतियों को पहनाया जाता है आर्टिफिशियल बेबी बंप और शुरू होता है 'प्रेग्नेंसी सिमुलेशन' का सफर। अब उठना, झुकना, चलना—सब मुश्किल हो जाता है। पत्नियों की हंसी थमने का नाम नहीं लेती, लेकिन असली इम्तिहान तब आता है जब डिवाइस के जरिए पतियों को झेलनी पड़ती है लेबर पेन की सिमुलेशन!

और जब लगता है कि एपिसोड का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है, तभी आता है सबसे भावुक पल। सुदेश और ममता, जिनकी शादी को 40 साल हो गए हैं, बताते हैं कि उनके पास अपनी शादी की कोई वीडियो नहीं है। शो उन्हें देता है एक अद्भुत तोहफा—एआई तकनीक से उनकी शादी को शानदार अंदाज में फिर से रचाया जाता है। जैसे ही उनके युवावस्था के एआई अवतार वरमाला डालते हैं और सात फेरे लेते हैं, सेट तालियों और जयकारों से गूंज उठता है। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन स्कोरबोर्ड के हिसाब से आखिर में किसकी मेहनत, समझदारी और हिम्मत इस जंग में जीत दिलाएगी?

नीविया बॉडी मिल्क प्रस्तुत करता है 'पति पत्नी और पंगाङ्क जोडियों का रियलिटी चेक'। को-पावर्ड बायः शुगर फ्री ग्रीन, राजधानी बेसन, कैडबरी डेयरी मिल्क, पोर होम एयर फ्रेशनर्स और एन्वी परफ्यूम्स। स्पेशल पार्टनर्सः विक्रम टी, कोलगेट और कैच मसाले। हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे, सिर्फ कलर्स पर।

शेरगढ़ पुलिस ने दबोचे पांच अन्तर्राज्यीय तस्कर, लाखों की अवैध शराब, ट्रक और कार बरामद

मथुरा (जीएनएस)। थाना शेरगढ़ क्षेत्र स्थित छाता रोड़ से पुलिस ने पांच अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से लाखों की अवैध शराब, एक ट्रक और एक कार बरामद हुई है। पुलिस ने बरामद शराब की कीमत करीब 6 लाख रूपए बतायी है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी शेरगढ़ प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ अवैध शराब तस्करों की तलाश में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि छाता रोड़ से होकर अवैध शराब की खेप लेकर तस्कर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। उसी दौरान अवैध शराब लेकर जा रहे

तस्करों को पुलिस ने छाता रोड़ स्थित तुलाराम की धर्मशाला के पास घेराबंदी करके अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर आबिद पुत्र दीन मोहम्मद, असलम (हरियाणा), साजिद पुत्र असलू निवासी तिगांव थाना पुन्हाना जिला नूंह मेवात (हरियाणा), यासिर पुत्र जान मोहम्मद निवासी नेमखेड़ा खोयरी थाना पुन्हाना जिला नूंह मेवात (हरियाणा) और शहजान पुत्र हनीफ निवासी जैत अलका थाना पुन्हाना जिला नूंह मेवात (हरियाणा) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए शातिरों के कब्जे से हरियाणा निर्मित अवैध शराब की 150 पेटी, 26 बोरे श्रीराम पॉली विनाइल क्लोराइड, तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक और एक कार महिन्द्रा टीयूवी कार बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

मृत्युभोज (तेरहवीं) से अच्छा श्रद्धांजलि सभा:पूर्व विधायक

-सावित्री बाई फुले को बताया शिक्षा की देवी
-ढ़ोंग, आडंबर व पाखंड पर किया जमकर प्रहार

(जीएनएस)।

फतेहपुर। संत गॉडगे कान्वेंट स्कूल प्रेमनगर की पूर्व प्रबंधिका स्वर्गीय गीता चौधरी के पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सोमवार को किया गया। इसमें पूर्व विधायक समेत संतों ने भाग लिया। संतों ने नशा न करने तथा पूर्व विधायक ने कुरीतियों और पाखंवाद पर जमकर प्रहार किया।

मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रामसजीवन निर्मल ने उक्त कार्यक्रम को सराहते हुए तेरहवीं भोज न कराने की नसीहत दी। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कुरीतियों, पाखंडों के बारे में विस्तृत जानकारियां प्रदान की। बताया कि मेरे बगल के पंडित जी घण्टी बजाते थे, मैं घण्टा बजाता था, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सरस्वती को नकारते हुए सावित्री बाई फुले को शिक्षा की देवी बताया। उन्होंने कहाकि कि सावित्री बाई फुले यदि न होतीं तो आज महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जातीं। यह अधिकार दिलाने में उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा

था। वह जब पढ़ाने जातीं थी तो उनके ऊपर उद्दंड किस्म के लोग कीचड़ फेंकते, पत्थर मारते और छीटाकसी किया करते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह पढ़ाने जाने के दौरान एक साड़ी थैले में रखकर स्कूल जाती थीं। बौद्धिस्ट देवीदीन मौर्य ने बाबा संत गॉडगे महराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रबंधक चौधरी आरएन मानव के द्वारा किये गए कार्यक्रम की प्रसंशा की, साथ ही साथ उन्होंने ढोंग और पाखण्ड से दूर रहने की नसीहत दी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विद्यालय प्रबंधक चौधरी आरएन मानव ने बताया कि पत्नी गीता चौधरी की मृत्यु के बाद कोई क्रिया कर्म नहीं किया। वह अच्छे कर्म करके स्वर्ग में विराजमान है। उन्होंने कहाकि हमें किसी की कही हुई बात को आंख बंद कर नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि अपने विवेकरूपी तराजू से तौलकर मानना चाहिए। व्यक्ति का कर्म ही प्रधान है, नकि कर्मकांड। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चक बसवा कबीर आश्रम के संत शंकर साहेब ने बताया कि पूर्व प्रबंधिका संतों का सदैव सम्मान करती रही हैं, उनकी जितनी प्रसंशा की जाय कम है। उन्होंने जातिपात का भेदभाव छोड़कर अपने मन को निर्मल करने की बात कही। इस अवसर पर छिटानीलाल निर्मल, आरडी चौधरी, देवीदीन मौर्य, दिलीप चौधरी, पवन निर्मल, लेखाधिकारी राजेश चौधरी, मक्खनलाल साहू, प्रिंयका चौधरी, राजकरन चौधरी, डॉ. रामबालक दिवाकर, लवकुश निर्मल प्रधान, शिवप्रकाश चौधरी एवं भजन-कीर्तन के कलाकार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।

अखंड डीप ज्योति कलश रथ यात्रा का भव्य स्वागत

(जीएनएस)।

धाता। कस्बा स्थित गायत्री शक्तिपीठ में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा अखंड दीप ज्योति कलश रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हरिद्वार से रवाना होकर यह दिव्य कलश यात्रा धाता पहुंची।

टोली नायक समर बहादुर सिंह, सह टोली नायक सुभाष तिवारी व सारथी सूर्य कुशवाहा के नेतृत्व में रथ यात्रा नगर में जैसे प्रवेश हुई तो श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नगरवासियों ने जयघोष के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया। जनजागरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 1926 में प्रज्ज्वलित अखंड दीप के शताब्दी वर्ष की तैयारी है। गायत्री परिवार के लिए बसंत पंचमी 2026 का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वंदनीय माताजी का जन्मोत्सव भी है तथा अखंड दीप प्रज्वलन के 100 वर्ष पूर्ण होंगे।

यात्रा फतेहपुर से होते हुए रक्षपालपुर, भीमपुर तिराहा, शुकुलपुर, कल्यानपुर कचरौली और दीप नारायण तिराहा होते हुए गायत्री शक्तिपीठ धाता पहुंची। जगह-जगह भक्तों ने गायत्री मंत्रोच्चार व पुष्पवर्षा से स्वागत किया। शक्तिपीठ में शाम को 1100 दीपों का प्रज्ज्वलन कर सामूहिक मंत्रजप एवं कलश पूजन हुआ।गायत्री शक्तिपीठ के ट्रस्टी रामानंद सिंह ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार आगामी शताब्दी वर्ष को ऐतिहासिक रूप से मनाने जा रहा है। इसके निमित्त देश-विदेश में कलश यात्राएं संचालित की जा रही हैं, ताकि अधिकाधिक श्रद्धालु अखंड दीप के दर्शन कर सकें। इस अवसर पर धाता , कौशांबी सहित आसपास के सभी गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गायत्री परिवार के सदस्य मौजूद रहे।